RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 01 MAY TO 07 MAY 2024 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 32 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

IPL और इलेक्शन से उछला GST कलेक्शन, पहली बार दो लाख करोड़ रुपये के पार

Page 2

पड़ोसी देशों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी

Page 4

मारुति, टाटा, हुंदै या टोयोटो... अप्रैल में किसकी कारें सबसे ज्यादा बिकीं, जानें कौन से मॉडल्स ने मचाई धूम

Page 7

editoria!

बढ़ता पारिवारिक ऋण

परंपरागत तौर पर भारतीय परिवारों में अधिक बचत करने तथा कम कर्ज लेने की प्रवृत्ति रही है, पर अब यह परिदृश्य बदलता जा रहा है. पिछले किस वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर 2023) में पारिवारिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 39.1 प्रतिशत के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. यह अनुपात एक वर्ष पहले 36.7 प्रतिशत रहा था. वर्ष 2021 के जनवरी-मार्च की अवधि में पारिवारिक ऋण का अनुपात 38.6 प्रतिशत था. इस कर्ज का 72 प्रतिशत हिस्सा गैर-आवासीय ऋण है, जो आवास के लिए हासिल किये जाने वाले कर्ज की तुलना में तेज गति से बढ़ता जा रहा है. आवास के कर्ज में वृद्धि 12.2 प्रतिशत रही, जबकि गैर-आवासीय ऋण में बढ़ोतरी 18.3 प्रतिशत हुई. मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड की हालिया रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि कर्ज के आंकड़े इंगित कर रहे हैं कि लोग परिसंपत्तियां खरीदने की अपेक्षा उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद या फिजूलखर्ची पर अधिक खर्च कर रहे हैं. कुछ अन्य अध्ययनों में पाया गया है कि ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, जो कर्ज चुकाने के लिए अधिक ब्याज दरों पर व्यक्तिगत ऋण ले रहे हैं. उपभोग भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है. हमारी अर्थव्यवस्था का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा उपभोग से संचालित होता है. यदि क्रय शक्ति बढ़ने या भविष्य को लेकर सकारात्मक विश्वास से उपभोग बढ़ता है, तो यह अच्छी बात है, लेकिन असुरक्षित ऋण बैंकों पर बोझ हो सकते है तथा वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम बन सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने अनेक बार क्रेडिट कार्ड बकाया, पर्सनल लोन, उपभोक्ता ऋण में बड़ी उछाल को लेकर चिंता जतायी है तथा बैंकों को सचेत रहने की सलाह दी है. पिछले वर्ष अनेक चेतावनियों के बाद रिजर्व बैंक ने असुरक्षित कर्ज देना बैंकों के लिए महंगा बना दिया था. कर्ज बढ़ने के साथ समय पर किस्त न भरने या डिफॉल्ट करने के मामले भी बढ़ रहे हैं, जो संभावित खतरे की ओर संकेत कर रहे हैं. मोतीलाल ओसवाल रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में पारिवारिक ऋण बहुत कम है, लेकिन परिवारों का असुरक्षित ऋण (बिना किसी गारंटी या गिरवी के) का स्तर ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बराबर है तथा अन्य कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से अधिक है. एक ओर परिवारों का कर्ज भार बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर उनकी बचत लगभग पांच दशक में सबसे कम स्तर पर है. परिवार के पास मौजूद कुल पैसे और निवेश में से देनदारियों को घटाने के बाद जो राशि बचती है, उसे पारिवारिक बचत कहते हैं. कर्ज बढ़ने और बचत घटने का हिसाब स्पष्ट है. इसीलिए हमारे पुरखे चेता गये हैं- तेते पांव पसारिए, जेती लंबी सौर.

ICRA: 104 अरब डॉलर पहुंच सकता है भारत का तेल आयात बिल

उच्च स्तर पर बनी रह सकती है क्रूड आयात पर निर्भरता

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत का शुद्ध कच्चा तेल आयात बिल चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 101-104 अरब डॉलर पहुंच सकता है, जो 2023-24 में 96.1 अरब डॉलर था। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा, भारत की क्रूड आयात पर निर्भरता उच्च स्तर पर बने रहने का अनुमान है। अगर रूसी कच्चे तेल की खरीद पर छूट मौजूदा निम्न स्तर पर बनी रहती है और क्रूड की औसत कीमत 85 डॉलर प्रति बैरल रही तो देश का आयात बिल 104 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। एजेंसी ने कहा, ईरान-इस्त्राइल संघर्ष बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि की आशंका है। अगर ऐसा हुआ तो शुद्ध तेल आयात के मूल्य पर दबाव बढ़ सकता है। भारत अपनी जरूरतों का 85 फीसदी से अधिक क्रूड आयात करता है।

0.3 प्रतिशत बढ़ सकता है कैड

एजेंसी के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में क्रूड की औसत कीमत में 10 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि से शुद्ध तेल आयात 12-13 अरब डॉलर बढ़ जाएगा। इससे जीडीपी के अनुपात में चालू खाते का घाटा (कैड) 0.3 फीसदी तक बढ़ जाएगा। अगर क्रूड 95 डॉलर प्रति बैरल पहुंचता है तो कैड बढ़कर जीडीपी के 1.5 फीसदी तक पहुंच सकता है। इक्रा ने अपने विश्लेषण के आधार पर कहा, रूसी कच्चे तेल आयात के कम मूल्य से वित्त वर्ष 2023-24 के 11 महीने (अप्रैल-फरवरी) में भारत को 7.9 अरब डॉलर की बचत होने की उम्मीद है। यह आंकड़ा 2022-23 में हुई 5.1 अरब डॉलर की बचत से अधिक है।

15.2 फीसदी घटा कच्चा तेल आयात 11 महीने में

इक्रा के मुताबिक, 2023-24 के पहले 11 महीनों में भारत के कच्चे पेट्रोलियम और इससे जुड़े उत्पादों के आयात में 15.2 फीसदी की गिरावट रही। इसकी प्रमुख वजह...कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में नरमी के साथ रियायती दर पर रूसी क्रूड की खरीद में वृद्धि रही। इस अवधि में मात्रा के लिहाज से भारत के कुल आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी बढ़कर 36 फीसदी पहुंच गई, जो वित्त वर्ष 2021-22 में महज 2 फीसदी रही थी। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत से आयात 34 फीसदी से घटकर 23 फीसदी रह गया।

पश्चिमी देशों के दबाव में रूस से नहीं लेते तेल तो ...

पिछले वर्ष भारत को होता 8 अरब डॉलर का नुकसान

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। भारत ने रूस के साथ लंबे समय के लिए तेल खरीद का समझौता किया हुआ है। इन समझौतों में भारत की कई तेल कंपनियां शामिल हैं। भारत ने पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस के साथ अच्छे रिश्ते रखे हैं और द्विपक्षीय व्यापार भी ऊंचाईयों पर है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद में बेतहाशा बढ़ोतरी की है। वहीं भारत ने अमेरिका को साफ तौर पर बता दिया था कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जरूरत के हिसाब से किसी भी देश से तेल की खरीदारी कर सकता है। भारत ने पश्चिमी देशों के दबाव में न आकर अच्छा मुनाफा कमाया है। अगर भारत पश्चिमी देशों के दबाव में आकर रूस से तेल नहीं खरीदता तो उसे पिछले वर्ष करीब 8 अरब डॉलर का नुकसान हो गया होता।

भारत ने की बचत- आईसीआरए रिसर्च ने बताया कि भारत ने 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2023-24 के 11 महीनों में तेल आयात में अनुमानित 7.9 बिलियन डॉलर की बचत की, जबकि पूरे 2022-23 में 5.1 बिलियन डॉलर की बचत हुई है। इस बचत से 2023-24 में भारत के चालू खाता घाटे-से-जीडीपी अनुपात में 15-22 आधार अंकों का कंप्रेशन होगा। कहा गया है कि अगर छूट के निम्न स्तर कायम रहते हैं, तो भारत का शुद्ध तेल आयात बिल 2023-24 में 96 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 101-104 बिलियन डॉलर हो सकता है, यह मानते हुए कि औसत कच्चे तेल की कीमत 85 डॉलर प्रति बैरल है।

बैंक नहीं वसूल पाएंगे आपसे महंगा ब्याज

RBI ने बैंकों को दिया ये सख्त निर्देश

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा महंगा ब्याज वसूलने पर सख्त एतराज जताया है। आरबीआई ने कई बैंकों के ब्याज वसूलने में अनुचित तौर-तरीके पर सोमवार को चिंता जताते हुए उन्हें सुधारात्मक कदम उठाने और अतिरिक्त शुल्क लौटाने का निर्देश दिया। आरबीआई के दायरे में आने वाली वित्तीय संस्थाओं (आरई) को उचित व्यवहार संहिता पर जारी दिशानिर्देशों में ऋण मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में पर्याप्त स्वतंत्रता देने के साथ ऋणदाताओं द्वारा ब्याज वसूलने में निष्पक्षता और पारदर्शिता की वकालत की गई है।

निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे

केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी करते हुए कहा कि इसके निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आरबीआई ने परिपत्र में कहा, '31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए विनियमित इकाइयों की भौतिक जांच के दौरान रिजर्व बैंक को ऋणदाताओं द्वारा ब्याज वसूलने में कुछ अनुचित गतिविधियों का सहारा लेने के उदाहरण मिले।' केंद्रीय बैंक ने सभी इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे ऋण वितरण के तरीके, ब्याज लगाने और अन्य शुल्कों के संबंध में अपने तौर-तरीकों की समीक्षा करें और जरूरी होने पर प्रणालीगत बदलाव जैसे कदम उठाएं। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों एवं अन्य कर्जदाताओं की जांच में पाया गया कि कई जगहों पर ऋण की मंजूरी की तारीख या ऋण समझौते के निष्पादन की तारीख से ब्याज वसूला जा रहा है, न कि ग्राहक को धन के वास्तविक वितरण की तारीख से। ऐसे भी मामले सामने आए जहां चेक की तारीख से ब्याज वसूला गया जबकि ग्राहक को चेक कई दिनों बाद सौंपा गया।

इस तरह उगाही कर रहे कुछ बैंक

आरबीआई ने कहा कि महीने के दौरान ऋण के वितरण या पुनर्भुगतान के मामले में, कुछ संस्थान बकाया अवधि के बजाय पूरे महीने का ब्याज ले रहे थे। वहीं कुछ मामलों में बैंक अग्रिम में एक या अधिक किस्तें जमा कर रहे थे लेकिन ब्याज वसूलने के लिए पूरी ऋण राशि की गणना कर रहे थे। आरबीआई ने कहा कि अनुचित तौर-तरीके और ब्याज वसूलने की ऐसी गैर-मानक गतिविधियां ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय निष्पक्षता और पारदर्शिता की भावना के अनुरूप नहीं हैं। रिजर्व बैंक ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा, 'विनियमित इकाइयों को इस तरह लिया गया अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य शुल्क ग्राहकों को वापस करने की सलाह दी जाती है।'

IPL और इलेक्शन से उछला GST कलेक्शन, पहली बार दो लाख करोड़ रुपये के पार

नई दिल्ली। एजेंसी

अप्रैल में रेकॉर्ड स्तर पर पहुंचा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन देश में तेज आर्थिक गतिविधियों का संकेत दे रहा है। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 2 लाख 10 हजार करोड़ रुपये रहा। यह अब तक का सबसे अधिक कलेक्शन है। इससे पहले पिछले साल अप्रैल का एक लाख 87 हजार करोड़ रुपये का आंकड़ा सबसे बड़ा था। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले महीने में रेकॉर्ड कलेक्शन के पीछे लोकसभा चुनाव और इंडियन

प्रीमियर लीग से जुड़ी हलचल का बड़ा योगदान रहा। इनके चलते देश में तमाम चीजों की खरीद-फरोख्त बढ़ी और उसका असर जीएसटी संग्रह में दिखा है। ताजा आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए फाइनैंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने दमदार आर्थिक गतिविधियों का हवाला दिया।' पर उन्होंने एक पोस्ट में कहा, 'जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपये के बेंचमार्क को पार कर गया। इकॉनमी में दमदार मोमेंटम और टैक्स कलेक्शन की अच्छी व्यवस्था के चलते ऐसा हुआ।' फाइनेंशल ईयर 2024 में 20.18 लाख करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन हुआ था। इस तरह ऐवरेज मंथली कलेक्शन 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2023 में 1.5 लाख करोड़ रुपये का ऐवरेज मंथली कलेक्शन हुआ था।

क्या कहते हैं जानकार

बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकनॉमिस्ट मदन सबनवीस ने कहा, 'अप्रैल में दमदार कलेक्शन के पीछे कई चीजों का योगदान है। फसलों की कटाई के साथ यह शादी-विवाह का सीजन भी है। अप्रैल में छुट्टियों में लोग सैर-सपाटे पर निकले और हॉस्पिटैलिटी पर खर्च बढ़ा। घ्रब्ध और आम चुनाव के चलते भी खर्च बढ़ा है। एक बात यह भी रही कि अप्रैल में रिफंड्स कम रहे। अच्छे जीएसटी कलेक्शन का सिलसिला मई में भी दिखेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस साल जीडीपी ग्रोथ 7.5% से अधिक रहने वाली है।'

क्या कहता है दमदार कलेक्शन

दमदार कलेक्शन इस बात का सबूत है कि लोग जमकर खरीद-फरोख्त कर रहे है और अप्रैल में यह सिलसिला तेज हुआ। टैक्स चोरी रोकने की कोशिशों का भी योगदान है। इस सिस्टम की कामयाबी को देखते हुए आने वाले समय में इसके दायरे में और उत्पादों को लाने और रेट्स में बदलाव पर विचार हो सकता है।

अब सभी मसाला बनाने वाली फैक्ट्रियों का होगा निरीक्षण, इस एजेंसी ने दिया है आदेश

नई दिल्ली। एजेंसी

एमडीएच (MDH) और एवरेस्ट (Everest) मसाले में कीटनाशी मिलने की खबर से तो आप अवगत होंगे ही। सिंगापुर और हांगकांग में इन दोनों कंपनियों के मसालों में कीटनाशी (Ethylene oxide) के अंश तय पैमाने से ज्यादा पाए जाने के बाद इनके मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यही नहीं, वहां जो कंसाइनमेंट पहुंच चुका है, उसे भी वापस लौटा दिया गया था। इसके बाद भारतीय एजेंसियां भी सक्रिय दिखती है। अब केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI ने स्पाइस मिक्स (Spice Mix) बनाने वाली सभी कंपनियों की फैक्ट्रियों में राष्ट्रव्यापी निरीक्षण का आदेश दिया है।

क्या दिया है आदेश

रायटर की एक खबर के मुताबिक भारत के खाद्य सुरक्षा नियामक इएफएसएसएआई ने गुरुवार को कहा कि उसने मसाला मिक्स बनाने वाली सभी कंपनियों पर राष्ट्रव्यापी परीक्षण और निरीक्षण का आदेश दिया है। FSSAI के इस आदेश से माना जा रहा है कि सरकार भारत से होने वाले पांच अरब डॉलर से भी ज्यादा के मसालों के निर्यात को बचाने के लिए कृतसंकल्प है। तभी तो इस क्षेत्र पर कार्रवाई बढ़ गई है।

क्या हुआ था पिछले महीने

हांगकांग ने पिछले महीने भारत के एमडीएच द्वारा बनाए गए तीन स्पाइस ब्लेंड और एवरेस्ट द्वारा बनाए गए फिश करी मसाला की बिक्री रोक दी थी। सिंगापुर ने एथिलीन ऑक्साइड के उच्च स्तर को चिह्नित करते हुए उसी एवरेस्ट स्पाइस मिक्स को वापस भेजने का आदेश दिया था। सिंगापुर सरकार का कहना था कि यह मसाला मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है। इसका लंबे समय तक उपयोग करने से कैंसर का खतरा हो सकता है।

लोकप्रिय हैं ये प्रोडक्ट

एवरेस्ट और एमडीएच के मसाले भारत में बेहद लोकप्रिय हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप में तो खूब बिकते ही हैं, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में भी खूब बेचे जाते हैं। इन कंपनियों ने कहा है कि उनके सभी मसाले सुरक्षित हैं। फिर भी, अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई खाद्य अधिकारियों ने कहा कि वे इस मामले पर अधिक जानकारी एकत्र कर रहे हैं। भारत ने तो पहले ही दो ब्रांडों के उत्पादों के परीक्षण का आदेश दिया था।

अब होगा एक्सटेंसिव इंस्पेक्शन

भारतीय खाद्य नियामक FSSAI ने अब अधिकारियों को घरेलू बाजार और विदेशी बाजार में बिक्री के लिए भेजे जाने वाले करी पाउडर और ब्लेंड मसाला मिक्स बनाने वालों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। इसी के साथ, पाउडर मसालों के लिए 'सभी विनिर्माण इकाइयों में व्यापक निरीक्षण, नमूनाकरण और परीक्षण' करने का भी आदेश दिया है।

क्या कहा है FSSAI ने

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने एक बयान में कहा, 'नमूने में लिए गए प्रत्येक उत्पाद का गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए विश्लेषण किया जाएगा।' एजेंसी ने कहा है कि एथिलीन ऑक्साइड की किसी भी उपस्थिति के लिए भी जांच की जाएगी। इस रसायन का उपयोग भारत में भी प्रतिबंधित है। एजेंसी का कहना है कि परीक्षण में जो भी अनियमितता पाई जाएगी, उस पर बाद में 'उचित कार्रवाई की जाएगी।

भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक

जियोन मार्केट रिसर्च Zion Market Research के अनुसार, भारत मसालों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक तो है ही, इसका सबसे बड़ा ग्राहक भी है। इसके साथ ही भारत ही मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। साल 2022 में इन पदार्थों का घरेलू बाजार 10.44 बिलियन डॉलर आंका गया था।

स्टेनलेस स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी चली विदेश, इंडोनेशिया में लगाएगी फैक्ट्री!

नई दिल्ली। एजेंसी

जिंदल स्टेनलेस ने अपनी मेल्टिंग और डाउनस्ट्रीम क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विस्तार और अधिग्रहण योजनाओं की घोषणा की है। यह देश की प्रमुख स्टेनलेस स्टील बनाने वाली कंपनी है। दुनिया में सबसे बड़े स्टेनलेस स्टील निर्माताओं में शुमार होने के उद्देश्य के साथ उसने ऐसा किया है। कंपनी ने स्टेनलेस स्टील में ग्लोबल लीडरशिप हासिल करने के लिए करीब 5,400 करोड़ रुपये की तीन स्तरीय निवेश रणनीति का ऐलान किया। जिंदल स्टेनलेस ने इंडोनेशिया में 12 लाख टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) निर्माण क्षमता वाली स्टेनलेस स्टील मेल्ट शॉप (एसएमएस) स्थापित और संचालित करने के लिए संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी ली है। इसमें 700 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने के साथ ही कंपनी की मेल्टिंग क्षमता 40 फीसदी बढ़कर 4.2 एमटीपीए हो जाएगी। कंपनी ने मेल्टिंग क्षमता में बढ़ोतरी की प्रक्रिया के तहत ओडिशा के जाजपुर में अपनी 'डाउनस्ट्रीम' लाइनों के विस्तार के लिए लगभग 1,900 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

क्रोमनी स्टील्स का करेगी अधिग्रहण

इसके अलावा कंपनी ने रेलवे साइडिंग, स्थिरता संबंधी परियोजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन जैसी बुनियादी ढांचा सुविधाओं की प्रगति के लिए लगभग 1,450 करोड़ रुपये तय किए हैं। कंपनी अप्रत्यक्ष अधिग्रहण सौदे के जरिये गुजरात के मुंद्रा में 0.6 एमटीपीए कोल्ड रोलिंग मिल की मालिक क्रोमेनी स्टील्स प्राइवेट (सीएसपीएल) में 54% इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। सौदे में करीब 1,340 करोड़ रुपये का परिव्यय होना है। इसमें 1,295 करोड़ रुपये का मौजूदा कर्ज और इक्विटी खरीद के लिए 45 करोड़ रुपये की शेष राशि शामिल है।

सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए सरकार की नई स्कीम, पहले से भी बड़ा पैकेज लाने की तैयारी

नई दिल्ली। एजेंसी

दुनियाभर में सेमीकंडक्टर चिप की मांग तेजी से बढ़ रही है और सरकार इस मौके के फायदा उठाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसके लिए सरकार ने दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ रुपये की एक योजना शुरू की थी। इसके तहत सेमीकंडक्टर कंपनियों को इन्सेंटिव दिया जा रहा है। भारी निवेश के कारण इस योजना का पैसा लगभग खत्म हो चुका है। अब सरकार इससे भी बड़ा पैकेज लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक नए पैकेज पर प्रारंभिक कार्य शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि यह पिछले पैकेज से काफी बड़ा होगा। लेकिन इसकी घोषणा आम चुनावों के बाद बनने वाली नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद ही की जाएगी।

एक सूत्र ने कहा, 'नया पैकेज नई सरकार के प्रमुख एजेंडे में से एक होगा और इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा।' उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर के लिए जो नए प्रस्ताव आ रहे हैं, उनके लिए नए पैकेज की आवश्यकता है। सूत्र ने कहा कि यह मामला नए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा, क्योंकि कुछ प्रस्ताव अग्रिम चरण में हैं और प्रोत्साहन के संदर्भ में सरकार से तत्काल आश्वासन की आवश्यकता होगी। दिसंबर 2021 के पैकेज की सफलता से सरकार नया पैकेज तैयार करने के लिए प्रेरित हुई है। खासकर अमेरिका और चीन जैसे देशों ने सेमीकंडक्टर में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़े पैकेज की घोषणा की है। मौजूदा योजना के तहत, सरकार डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटर्स को परियोजना की लागत का 50% तक वित्तीय सहायता देती है। भारी मात्रा में निवेश आने के बाद इस योजना का पैसा लगभग खत्म हो गया है।

किन-किन कंपनियों ने दिया प्रस्ताव

सरकार कई दशकों से देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में काम कर रही है लेकिन हाल में जाकर उसे सफलता मिली है। अमेरिकी कंपनी माइक्रोन ने पिछले साल जून में गुजरात में 22,500 करोड़ रुपये की लागत से टेस्टिंग और पैकेजिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की थी। यह भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश करने वाले पहली कंपनी थी। इस साल फरवरी में करीब 1.3 लाख करोड़ रुपये के तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ताइवानी की पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प के साथ गुजरात के धोलेरा में देश की पहली सेमीकंडक्टर फैब यूनिट स्थापित करेगी। इस पर 91,000 करोड़ रुपये खर्च आने की संभावना है। इसी तरह टाटा असम के मोरीगांव में 27,000 करोड़ रुपये की लागत से सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (TSAT) यूनिट लगाएगी। साथ ही सीजी पावर भी जापान की कंपनी Renesas Electronics और थाईलैंड की स्टार्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स के साथ 7,600 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट लगाने जा रही है।

सरकार को अब इस बारे में कई नए प्रस्ताव मिले हैं। सूत्रों का कहना है कि इन पर चर्चा बहुत आगे बढ़ चुकी है। जापान की एक कंपनी ने डिस्प्ले फैब यूनिट का प्रस्ताव दिया है। इसमें 40,000 करोड़ रुपये तक का निवेश हो सकता है। इसके अलावा इजरायल की चिप निर्माता कंपनी टावर सेमीकंडक्टर्स की भी भारत में 90,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है। सूत्र ने कहा कि प्रस्तावों को तत्काल समाधान की आवश्यकता है क्योंकि इन्सेंटिव सपोर्ट पर सरकार से स्पष्टता चाहती हैं। सेमीकंडक्टर चिप को नए जमाने का ऑयल कहा जा रहा है क्योंकि कई तरह की इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े-बड़े देश इसकी सप्लाई चेन पर कंट्रोल करना चाहते हैं।

सेविंग अकाउंट पर चार्ज में बढ़ोतरी

न्यू केवायसी नियम समेत ये 5 बड़े बदलाव आज से लागू

आईपीटी नेटवर्क

अप्रैल का महीना खत्म हो गया है। आज से मई का नया महीना शुरू हो गया है। इसके साथ ही रुपये-पैसे से जुड़े कई अहम नियम में बदलाव भी हुआ है। आइए जानते हैं कि 1 मई से कौन-कौन से अहम नियम बदल गए हैं और उन नियमों के बदलने से आपकी जेब पर कितना असर होगा।

1. ICICI Bank सेविंग अकाउंट पर शुल्क में बदलाव

आईसीआईसीआई बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट पर लगने वाले चार्ज में बदलाव किया है। यह आज यानी 1 मई लागू हो गया है। बदलाव के तहत डेबिट कार्ड पर प्रति व ष 200 रुपये तक की वार्षिक फीस शामिल है। ग्रामीण स्थानों के लिए, शुल्क 99 रुपये प्रति वर्ष है। चेक बुक पर, एक वर्ष में 25 चेक लीफलेट के लिए शुल्क शून्य होगा और इससे अधिक, बैंक 4 रुपये प्रति लीफ चार्ज करेगा। बैंक तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) लेनदेन के लिए हस्तांतरित राशि के अनुसार प्रति लेनदेन 2.5 रुपये से 15 रुपये के बीच शुल्क लेगा। वित्तीय कारणों से प्रति ईसीएस/एनएसीएच डेबिट रिटर्न पर 500 रुपये का जुर्माना शुल्क भी लगेगा। एक ही शासनादेश के लिए प्रति माह अधिकतम तीन बार वसूली की जाएगी।

2. PAN–MF फोलियो में नाम गलत होने पर आवेदन रद्द होगा

आज से अगर म्यूचुअल फंड आवेदन पर आपका नाम आपके पैन (स्थायी खाता संख्या) कार्ड से मेल नहीं खाता है, तो आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। आधिकारिक रिकॉर्ड में आपका नाम कैसे दिखाई देता है, इसे स्पष्ट बनाने के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड-अनिवार्य केवाईसी नियम कहते हैं कि आपका नाम एक समान होना चाहिए। अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड फोलियो में निवेश कर रहे हैं, तो आपका नाम और जन्मतिथि आपके पैन पर और आपके आयकर रिकॉर्ड में दिखाई देने वाली तारीख के समान होनी चाहिए।

3. YES Bank मिनिमम बैलेंस के नियम में बदलाव किया

यस बैंक ने आज से सेविंग अकाउंट पर लगने वाले विभिन्न चार्ज में बदलाव का ऐलान किया है। बैंक ने बचत खातों में निर्धारित औसत मासिक शेष (एएमबी) से कम बनाए रखने पर अधिकतम शुल्क बढ़ा दिया है। बैंक 250 रुपये से 1,000 रुपये के बीच शुल्क लेगा। पहले, शुल्क 250 रुपये से 750 रुपये के बीच थे। शुल्क बचत खाते के प्रकार, बैंक शाखा के स्थान और खाते में कमी राशि के आधार पर भिन्न होते हैं। बैलेंस कम रहने के कारण ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस) रिटर्न के साथ, बैंक अब पहली बार में 500 रुपये का शुल्क लेगा। दूसरे रिटर्न के बाद से बैंक 550 रुपये चार्ज करेगा।

4. यूटिलिटी बिल चुकाना पड़ेगा महंगा

आज से यूटिलिटी बिल चुकाना पड़ेगा महंगा। बैंक 1 मई से क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल भुगतान पर 1इ एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। आपको बता दूं कि यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने घोषणा किया है कि वे 1 मई, 2024 से अपने क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल के भुगतान पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लेंगे। अगर आपके पास यस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो 15,000 रुपये की मुफ्त उपयोग सीमा होगी। वहीं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए 20,000 रुपये है। इससे अधिक के बिल भुगतान पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा।

5. एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव

1 मई से एलपीजी सिलेंडर और एटीएफ की कीमत में भी बदलाव देखने को मिलेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत तय करती हैं। कंपनियां 14 किलो वाले घरेलू और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम तय करती हैं। सीएनजी और पीएनजी की कीमतें भी तय होती हैं।

टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर यह कैसी सजा!

5 लाख लोगों का सिम ब्लॉक करेगी पाकिस्तान सरकार

इस्लामाबाद। एजेंसी

पाकिस्तान सरकार ने टैक्स नहीं भरने वाले लोगों को नई तरह की सजा देने का फैसला लिया है। सरकार ऐसे लोगों के सिम कार्ड ब्लॉक कर रही है। पाकिस्तान में 2023 में टैक्स रिटर्न नहीं भरने वाले पांच लाख से ज्यादा लोगों के सिम कार्ड फ्रीज करने का फैसला सरकार ने लिया है। संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) ने एक आयकर सामान्य आदेश (आईटीजीओ) में कहा कि 5,06,671 लोगों के मोबाइल सिम कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं। अपने कर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहे इन लोगों के सिम तब तक फ्रीज किया जाएगा जब तक कि उन्हें एफबीआर या उस व्यक्ति पर अधिकार रखने वाले राजस्व आयुक्त की ओर से बहाल नहीं किया जाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) और सभी दूरसंचार प्रदाताओं को आयकर सामान्य आदेश (आईटीजीओ) संख्या 01/2024 को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया। इस आदेश के तहत उन्हें बोर्ड की ओर से बताए गए लोगों के सिम कार्ड पर प्रतिबंध लगाना होगा और 15 मई तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी होगी। एफबीआर ने कहा है 24 लाख संभावित करदाताओं की खोज की गई है, जो पहले टैक्स सूची में नहीं थे। एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार कई बार इन व्यक्तियों को नोटिस भेजा गया लेकिन इनकी ओर से टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है।

24 लाख में से 5 लाख लोगों पर कार्रवाई

एफबीआर ने टैक्स नहीं भरने वाले 24 लाख लोगों में से एक मानदंड के आधार पर सिम ब्लॉकिंग के लिए 5 लाख लोगों को चुना। इन लोगों ने पिछले तीन सालों में टैक्स योग्य आय घोषित की थी और वित्तीय वर्ष 2023 के लिए अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं की थी। बोर्ड अधिकारियों ने कहा है कि सिम कार्ड प्रतिबंध एक नया सरल तरीका है, जिससे कम आय वाले लोगों को अपने कर रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़ाया जाए।

अमेरिका में आया ब्याज दर पर फैसला, फेड ने महंगाई पर किया खास इशारा

एजेंसी

शेयर बाजार के निवेशकों को इस बार भी अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने निराश किया है। यूएस फेड ने इस बार भी प्रमुख ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 5.25 फीसदी से 5.50 फीसदी पर यथावत रखा है। साथ ही अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने महंगाई के मोर्चे पर प्रोग्रेस में सुस्ती का भी इशारा किया है। बुधवार रात करीब 12 बजे यूएस फेड ने ब्याज दरों पर अपना फैसला सुनाया। इसके अलावा यूएस फेड ने ट्रेजरी रिडेम्पशन कैप में की कटौती की है।

ब्याज दर में बदलाव नहीं करने का था अनुमान- अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की दो दिन की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी बैठक बुधवार देर रात खत्म हो गई। अनुमान था कि यूएस फेड बेंचमार्क ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा और इन्हें लगातार छठी बैठक में भी 5.25 फीसदी से 5.50 फीसदी पर यथावत रखेगा। अमेरिकी शेयर बाजार यानी वॉल स्ट्रीट का यही अनुमान था। ब्याज दर निर्धारित करने वाले पैनल ने साल की दूसरी पॉलिसी तय करने वाली बैठक 20 मार्च को की थी। इसमें पॉलिसी दरों को 23 साल के उच्च स्तर पर यथावत रखने के लिए वोट किया गया था। लेकिन इसमें कहा कि उसे यह उम्मीद नहीं है कि टार्गेट रेंज को कम करना तब तक उचित होगा, जब तक कि उसे यह विश्वास न हो जाए कि महंगाई दर लगातार दो प्रतिशत की ओर बढ़ रही है।

जुलाई 2023 से ब्याज दर में नहीं किया बदलाव- महंगाई दर पर काबू पाने के लिए यूएस फेड ने मार्च 2022 से पॉलिसी रेट को बढ़ाना शुरू किया था। इसने इसमें 5.25 फीसदी की बढ़ोतरी की। इसके बाद अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने जुलाई 2023 से प्रमुख ब्याज दर को बरकरार रखा है।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभियोजन अधिकारियों की सूची जारी

लॉ इसी संस्थान के 9 विद्यार्थी एडीपीओ में चयनित

अधिवक्ता पंकज वाधवानी के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों का सिलेक्शन

इंदौर। एजेंसी

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जिला अभियोजन अधिकारी एडीपीओ कि साक्षात्कार सूची में चयनित उम्मीदवारों के परीक्षा परिणाम की घोषणा की गई जिसमें एडवोकेट पंकज वाधवानी के मार्गदर्शन में 9 विद्यार्थियों का जिला अभियोजन अधिकारी के रूप में चयन हुआ है। संस्थान में सभी चयनित विद्यार्थियों का सम्मान किया गया।

यह होता है एडीपीओ का काम

जिला अभियोजनअधिकारी राज्य सरकार की ओर से अभियोजन अर्थात पुलिस की तरफ से मजिस्ट्रेट न्यायालय में राज्य का पक्ष रखते हैं और इनका कार्य होता है अपराधियों को सजा दिलवाने इसके लिए अभियोजन साक्ष के गवाही कराने का मुख्य काम एडीपीओ का होता है।

कॉमर्शियल वाहनों की आसान फाइनेंसिंग के लिए

टाटा मोटर्स ने साउथ इंडियन बैंक के साथ समझौता ज्ञापन किया

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

भारत में कॉमर्शियल वाहनों के सबसे बड़े निर्माता, टाटा मोटर्स ने कॉमर्शियल वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं और डीलरों को फाइनेंस के सुविधाजनक समाधान देने के लिए साउथ इंडियन बैंक के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। साउथ इंडियन बैंक कंपनी के सभी तरह के कॉमर्शियल वाहनों की खरीदारी के लिए उपभोक्ताओं को फाइनेंसिंग की सुविधा देगा और उपभोक्ताओं को बैंक के व्यापक नेटवर्क और खसतौर से बनाई गई भुगतान की आसान योजनाओं से फायदा मिलेगा। यह सहयोग डीलरशिप को बेहतर सहयोग देने, वृद्धि को बढ़ावा देने, कोलेटरल की जरूरतों को कम से कम करने, व्याज दर में कटौती करने और ऋण की प्रक्रिया को सुचारू बनाने में किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों को दर्शाता है। साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ श्री पी. आर. शेषाद्रि ने विकास के बारे में कहा, 'माउथ इंडियन बैंक में, हम सुरक्षित, फुर्तीला और गतिशील बैंकिंग माहौल बनाने के लिए समर्पित हैं, जो गाडियों के मालिकों और डीलरों की जरूरत को पूरा कर सकें। टाटा मोटर्स के साथ हमारे समझौते ने हमें कमर्शल वाहन के डीलरों और उपभोक्ताओं को वाहन को फाइनेंस करने के लिए आसान और सुविधाजनक समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाया है। हमें पूरी उम्मीद है कि टाटा मोटर्स के साथ हमारी साझेदारी से फाइनेंसिंग के बेहतरीन समाधान मिलेंगे, जो इंडस्ट्री में उत्कृष्टता के नए मानदंड स्थापित करेंगे।' टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स में ट्रक्स डिविजन के वाइस प्रेसिडेंट और बिजनेस हेड श्री राजेश कौल ने इस साझेदारी के बारे में कहा, 'हम प्रतिष्ठित माउथ इंडियन बैंक के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा कर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। हमारे उपभोक्ताओं के लिए, कॉमर्शियल वाहन खरीदने के लिए फाइनेंसिंग समाधानों तक आसान पहुंच उनके परिचालन की प्रमख प्राथमिकताओं में से एक है।

पड़ोसी देशों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी

नई दिल्ली। एजेंसी

नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से पिछले 10 वर्षों में किए जा रहे आर्थिक सुधारों के कारण भारत बड़ी छलांग लगाते हुए दुनिया की पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के दायरे से आगे निकल गया। साथ ही आईएमएफ डेटा विश्?लेषण करने से पता चलता है कि अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में देश का तुलनात्मक प्रदर्शन भी बेहतर हो गया है, जो पहले नहीं था।

जीवन स्तर में हो रहा सुधार

उच्च प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बढ़ने का मतलब यह भी है कि लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा है। आईएमएफ के आंकड़ों से पता चलता है कि 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 635 डॉलर थी, जो बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान द्वारा 'उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं' के रूप में सूचीबद्ध 150 देशों के लिए औसत प्रति व्यक्ति जीडीपी 1,790 डॉलर यानी 35 प्रतिशत है। इन समकक्ष देशों में चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मध्य पूर्व के साथ-साथ पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्से शामिल हैं।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट में बताया गया कि 35 प्रतिशत का यह आंकड़ा 2014 तक घटकर 30 प्रतिशत रह गया, जिससे पता चलता है कि भारत बेहतर प्रदर्शन करने वाले इन 150 देशों की तुलना में अपेक्षाकृत गरीब हो गया था। हालांकि, आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार, यह अनुपात 2014 में 30 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 37 प्रतिशत हो गया। 2024 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़कर 2,850 डॉलर हो गई है, जो इसके समकक्ष देशों के लिए 6,770 डॉलर का 42 प्रतिशत है। इसका मतलब यह है कि पिछले 10 वर्षों में भारत का आर्थिक प्रदर्शन अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर हो जाने से अंतर कम हो गया है।

दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था

आईएमएफ के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 2004 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार चीनी अर्थव्यवस्था का 37 प्रतिशत था, लेकिन 2014 तक यह घटकर मात्र 19 प्रतिशत रह गया, क्योंकि चीन बहुत अधिक विकास दर हासिल कर रहा था। हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था चीन की तुलना में बहुत तेज विकास दर से बढ़ रही है, बाजी पलट रही है और अर्थव्यवस्था का सापेक्ष आकार 22 प्रतिशत तक बढ़ गया है। भारत अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और चीन कम्युनिस्ट देश की तुलना में अर्थव्यवस्था के सापेक्ष आकार में पिछड़ रहा है। मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर भारत अब जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और जो समान रूप से महत्वपूर्ण है, वह यह है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, जो लोगों के बेहतर जीवन स्तर को दर्शाता है।

ई-वाणिज्य केंद्र विकसित करना नई सरकार के 100 दिन के एजेंडे में हो सकता है शामिल, जानें डिटेल

नई दिल्ली। एजेंसी

वाणिज्य मंत्रालय की शाखा विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) पहले से ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और वित्त मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों के साथ ई-वाणिज्य माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदमों पर काम कर रही है। ऑनलाइन माध्यम से भारत के निर्यात बढ़ाना नई सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकता है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा देश भर में ई-वाणिज्य केंद्र विकसित करने का खाका भी तैयार किया जा सकता है।

निर्यात को मिलेगा बढ़ावा

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि वाणिज्य मंत्रालय की शाखा विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) पहले से ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और वित्त मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों के साथ ई-वाणिज्य माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदमों पर काम कर रही है क्योंकि इस क्षेत्र में निर्यात के बड़े अवसर हैं। यह कवायद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मंत्रालयों को नई सरकार के लिए 100 दिन की योजना तैयार करने को कहा गया है।

लोकसभा चुनाव

भारत में सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को शुरू हुए। मतगणना चार जून को होगी। अधिकारी ने कहा कि ये केंद्र ई-वाणिज्य माध्यमों से निर्यात को और बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। उद्योग जगत के एक विशेषज्ञ के अनुसार, ऐसे केंद्र में निर्यात मंजूरी को सुगम बनाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें भंडारण सुविधाएं, सीमा शुल्क मंजूरी, रिटर्न प्रोसेसिंग, लेबलिंग, टेस्टिंग और रीपैकेजिंग की भी सुविधा हो सकती है।

भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा कि यह ऐसा क्षेत्र होगा जो ई-वाणिज्य कार्गो के निर्यात और आयात को सुविधाजनक बनाएगा और काफी हद तक पुनः आयात की समस्या का समाधान करेगा क्योंकि ई-वाणिज्य में करीब 25 प्रतिशत माल पुनः आयात किया जाता है। सीमा पार ई-वाणिज्य व्यापार पिछले वर्ष करीब 800 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था। इसके 2030 तक 2000 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) संतोष कुमार सारंगी ने हाल ही में कहा था कि ई-वाणिज्य माध्यम से निर्यात बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।

दुनिया की सबसे नई करेंसी जारी, सरकारी विभागों ने ही स्वीकारने से किया इनकार

नई दिल्ली। एजेंसी

जिम्बाब्वे ने मंगलवार को एक नयी मुद्रा 'जिग' का प्रचलन शुरू किया। इस मुद्रा को पुरानी मुद्रा की जगह लाया गया है, जो मूल्यह्रास और लोगों का भरोसा खत्म हो जाने से प्रभावित हुई है। अप्रैल की शुरुआत में जिग को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेश किया गया था, लेकिन अब लोग बैंकनोट और सिक्कों के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दक्षिणी अफ्रीकी देश की लंबे समय से चल रहे मुद्रा संकट को रोकने की ताजा कोशिश है। सरकार ने पहले जिम्बाब्वे डॉलर को बदलने के लिए विभिन्न विचार पेश किए थे, जिसमें मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सोने के सिक्के और एक डिजिटल मुद्रा को लाने जैसे विकल्प शामिल थे। जिग, जिम्बाब्वे गोल्ड का संक्षिप्त रूप है और देश के स्वर्ण भंडार द्वारा समर्थित है। हालांकि, इसके बावजूद लोग इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ सरकारी विभागों ने भी इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

2009 के बाद छठी करेंसी

जिग छठी मुद्रा है, जिसका उपयोग जिम्बाब्वे ने 2009 में जिम्बाब्वे डॉलर के पतन के बाद से किया है। इस संकट से निपटने के लिए पहले अमेरिकी डॉलर को वैध मुद्रा का दर्जा दिया गया, फिर उस पर प्रतिबंध लगाया गया और फिर प्रतिबंध हटाया गया। लोग अभी भी जिग को लेने से इनकार कर रहे हैं। उन्हें अमेरिकी डॉलर अभी भी सुरक्षित लग रहा है। सरकार ने गैस स्टेशनों जैसे कुछ व्यवसायों को जिग को स्वीकार करने से मना करने की अनुमति दी है। पासपोर्ट विभाग जैसे कुछ सरकारी कार्यालय भी केवल अमेरिकी डॉलर स्वीकार कर रहे हैं।

5 अरब परसेंट बढ़ी महंगाई

2009 में जिम्बाब्वे में महंगाई 50 अरब परसेंट बढ़ गई जिसके बाद वहां अर्थव्यवस्था का पतन हो गया। इसे जिंदा करने के लिए कई बार करेंसी जारी की गई। लेकिन अभी तक वहां के हालात सुधरे नहीं है। जिम्बाब्वे ने एक बार अमेरिकी डॉलर को भी अपने यहां की करेंसी बनाया था। इस पर बाद में प्रतिबंध लगा दिया गयाय़ फिर यह प्रतिबंध हटा भी दिया गया है। इस नई करेंसी पर अब वहां के लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, एक सब्जी विक्रेता ने कहा कि वह भले अपनी सब्जियां नहीं बेचेगा लेकिन नई करेंसी को स्वीकार नहीं करेगा।

सोना खरीदारों को राहत, मंगलवार को सस्ता हो गया गोल्ड

नई दिल्ली। एजेंसी

सोने की कीमतों में मंगलवार को गिरावट देखी गई है। इस कारण 24 कैरेट गोल्ड का रेट गिरकर 71,960 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर ये जानकारी दी गई। वहीं, चांदी की कीमत 81,000 रुपये प्रति किलो के करीब बनी हुई है।

क्या है 22,20,18 और 14 कैरेट का भाव?

इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 22 कैरेट सोने का भाव 70,240 रुपये प्रति 10 ग्राम, 20 कैरेट सोने का भाव 64,050 रुपये प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट सोने का भाव 58,290 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 46,420 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने और चांदी के दाम

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखी जा रही है। 24 कैरेट सोने का दाम 1.49 प्रतिशत गिरकर 2,322 डॉलर प्रति औंस चल रहा है। वहीं, चांदी 3 प्रतिशत की गिरावट के साथ 26 डॉलर प्रति औंस पर है। सोने और चांदी की कीमत में गिरावट की वजह फेड की ओर से ब्याज दर कम किए जाने की संभावना को माना जा रहा है।

वायदा में सोने और चांदी का भाव

वायदा बाजार में सोने और चांदी में गिरावट देखी जा रही है। सोने का 05 जून, 2024 का कॉन्ट्रैक्ट 0.91 प्रतिशत की गिरावट के साथ 70,947 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है। चांदी का 05 जुलाई, 2024 का कॉन्ट्रैक्ट 1.60 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,164 प्रति किलो पर बना हुआ है। वायदा बाजार में गिरावट का कारण ट्रेडर्स की ओर से पॉजीशन का कम करना है।

क्यों बढ़ रहा जीएसटी कलेक्शन? सरकार का खजाना इतना भरा कि टूट गए सारे रिकॉर्ड

नई दिल्ली। एजेंसी

अप्रैल 2024 में रिकॉर्ड 2.10 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इससे पहले अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ का सर्वाधिक जीएसटी प्राप्त हुआ था। आर्थिक मोर्चे पर देश ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अप्रैल 2024 में रिकॉर्ड 2.10 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह पहली बार है जब जीएसटी कलेक्शन ने दो लाख करोड़ के स्तर को पार किया है। इससे पहले अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपये का सर्वाधिक जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ था।

घरेलू लेन-देन और आयात में इजाफा

वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, घरेलू लेन-देन में 13.4% और आयात में 8.3% की बढ़ोतरी होने से जीएसटी कलेक्शन में यह जबरदस्त उछाल आया है। सकल जीएसटी कलेक्शन में सालाना आधार पर 12.4 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। रिफंड के बाद शुद्ध जीएसटी आय 1.92 लाख करोड़ की रही है। इसमें सालाना आधार पर 17.1 प्रतिशत का उछाल आया है। वहीं, मार्च के महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.78 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जबकि एक साल पहले अप्रैल 2023 में यह 1.87 लाख करोड़ रुपये था।

मासिक औसत में लगातार बढ़ोतरी

कर विशेषज्ञ योगेंद्र कपूर ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन विकास के मोर्चे पर स्वस्थ आर्थिक गति का संकेत देता है। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के शुरुआती दौर में इसका औसत मासिक कलेक्शन करीब 85,000 से 95,000 करोड़ रुपये था। जीएसटी प्रणाली में लगातार हुए सुधारों से जीएसटी कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में औसत मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.68 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, जो इससे पहले के वित्त वर्ष में 1.5 लाख करोड़ रुपये था। अब यह औसत बढ़कर 1.80 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है।

आर्थिक गतिविधियों में तेजी से यह उपलब्धि हासिल कीः सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी और कर कलेक्शन में दक्षता के दम पर माल एवं सेवा कर कलेक्शन दो लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। सीतारमण ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर इस मील के पत्थर को हासिल करने में राजस्व विभाग के केंद्रीय और राज्य अधिकारियों तथा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के ईमानदार और सहयोगात्मक प्रयासों' की सराहना की। सीतारमण ने यह भी कहा, आईजीएसटी निपटान को लेकर राज्यों का कोई बकाया नहीं है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

1. टैक्स चोरी करना अब संभव नहीं

जीएसटी एक्सपर्ट और सीए, शिल्पी गुप्ता ने हिन्दुस्तान को बताया कि जीएसटी अब पूरी तरह से ऑटोमेटेड मोड में काम कर रहा है। इसके चलते अब टैक्स चोरी करना या फर्जीवाड़ा करना संभव नहीं है। वहीं, विभाग ने भी कर चोरी पर सख्ती बढ़ाई है। देश में कई जगह छापेमारी कर टैक्स चोरी पकड़ी गई है। इन सब कारणों से जीएसटी क्लेशन लगातार बढ़ रहा है।

2. आईटीसी के फर्जीवाड़े पर लगाम का असर

जीएसटी विशेषज्ञ ब्रिजेश वर्मा ने बताया कि अब बिजनेस कम्युनिटी सरकार की मंशा को समझ गई है। जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन उसी का परिणाम है। सरकार ने पिछले कुछ समय से जो सख्ती दिखाई है, उससे आईटीसी के हो रहे फर्जीवाड़े पर कुछ हद तक लगाम लग गई है।

अब भी हम चीन पर निर्भर! धड़ल्ले से मंगाए जा रहे हैं ये सामान... क्या भारत के पास नहीं है विकल्प?

आत्मनिर्भर भारत मिशन के बावजूद, देश में चीन से आयात किए जाने वाले सामान की हिस्सेदारी कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। अभी ऐसा कोई आंकड़ा तो सामने नहीं आया है कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के बिना ये हिस्सेदारी कितनी ज्यादा बढ़ सकती थी, लेकिन फिलहाल मौजूद आंकड़ों के मुताबिक चीन से आने वाले औद्योगिक सामान के आयात में तेजी जारी है. आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी उरुँट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के औद्योगिक सामान आयात में चीन की हिस्सेदारी बीते 15 साल में 21 फीसदी बढ़कर 30 परसेंट हो गई है।

कुछ चीजों के लिए अब भी चीन पर निर्भर

इस आयात (ध्र्ीं घ्स्ज्ीं ण्र्पीं) में बढ़ोतरी की मुख्य वजह टेलीकॉम, मशीनरी और इलेक्ट्रानिक्स जैसे चीन के औद्योगिक सामानों पर भारत की बढ़ती निर्भरता है। इन सामानों का चीन से भारत का व्यापार घाटा बढ़ाने में भी बड़ा योगदान है। उरुँट ने कहा कि चीन के साथ भारत का बढ़ता व्यापार घाटा चिंता का विषय है. देश की चीन पर बढ़ती निर्भरता रणनीतिक तौर पर भी भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है, क्योंकि इससे आर्थिक के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सीधा असर होता है।

GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2024 तक चीन को भारत का निर्यात सालाना करीब 16 अरब डॉलर पर स्थिर रहा है। जबकि चीन से भारत को किए जाने वाला आयात 2018-19 में 70.3 अरब डॉलर के मुकाबले 2023-24 में बढ़कर 101 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है।

चीन से निर्यात के मुकाबले आयात में इजाफा

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन से आयात में ये बढ़ोतरी भारत के कुल आयात में हुए इजाफे के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ रही है। भारत में चीन का निर्यात बाकी सभी देशों से कुल आयात के मुकाबले 2.3 गुना तेजी से बढ़ रहा है. 2023-24 में भारत का कुल व्यापारिक आयात 677.2 अरब डॉलर था जिसमें से 101.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर चीन से आया था।

GTRI ने इस मुद्दे को चिंताजनक बताते हुए भारत सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं, जिनमें कहा गया है कि सरकार और उद्योगों को अपनी आयात रणनीतियों पर फिर से गौर करना चाहिए. इसके साथ ही सप्लाई चेन के डायवर्सिफिकेशन पर भी इन्हें ध्यान देना चाहिए. GTRI के मुताबिक इस कदम से ना केवल आर्थिक जोखिम कम किए जा सकेंगे बल्कि घरेलू उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसी एक देश पर से भारत की आयात के लिए निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। वैसे भी अगर ये एक देश चीन है तो भारत को यहां पर खासकर के काम करना होगा क्योंकि चीन और भारत के बीच भू-राजनीतिक तनाव भी एक बड़ा मुद्दा है।

दुबई में एक बार फिर जल प्रलय का खतरा

यूएई सरकार की जनता से अपील- सावधानी बरतें, घरों में रहें

दुबई। एजेंसी

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) इस हफ्ते एक बार फिर से भारी बारिश का सामना कर सकता है। इसे देखते हुए सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने और बेवजह घर से ना निकलने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को उम्मीद है कि मौसम की स्थिति पिछले महीने की तरह गंभीर नहीं होगी लेकिन सुरक्षा संबंधी सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनसीईएमए) ने बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए बैठक की है। बैठक में यूएई के आंतरिक मंत्रालय (एमओआई), राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (एनसीएम) और दूसरे सरकारी विभागों के अफसर भी शामिल थे।

अरब बिजनेस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, परेशानी को कम करने के लिए और व्यवसाय को कम से कम नुकसान हो, इस पर चर्चा की गई। इस चीजों को देखते हुए मौसम की स्थिति पर बारीकी से निगरानी रखने के महत्व पर जोर दिया गया। एनसीएम ने बताया कि बीते महीने जिस तरह

से भारी बारिश हुई, उस तरह से मौसम रहने की इस बार उम्मीद नहीं है। बुधवार रात से गुरुवार तक संयुक्त अरब अमीरात के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होगी। बारिश के साथ कुछ इलाकों में ओले गिरने और बिजली कड़कने की संभावना है। एनसीएम की ओर से कहा गया है कि सभी सावधानी रखें लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

शनिवार तक जारी रह सकती है बारिश

शुक्रवार और शनिवार को बादल छंटने लगेंगे और हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। आंतरिक मंत्रालय ने बारिश के पूर्वानुमान पर कहा है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए सर्वोच्च समिति, मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में काम कर रही है। टीम मौसम की स्थिति के विकास और अपडेट की लगातार निगरानी कर रही है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। मंत्रालय ने बताया है कि बारिश से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सभी जरूरी उपाय किए हैं।

यूएई में समुदाय की सुरक्षा और जीवन और संपत्ति की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए एमओआई ने जनता से सावधानी बरतने, सुरक्षा मानकों और दिशानिर्देशों का पालन करने, सक्षम अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने, अफवाहों को प्रसारित करने से बचने और जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया है। ऊर्जा मंत्रालय ने मौसम में बदलाव को देखते हुए जल भंडारण में अपनी दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से सड़कों, साथ ही बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 'गुड न्यूज'

2024-25 में GDP ग्रोथ की रफ्तार पर NCAER ने दिया बड़ा अपडेट

नई दिल्ली। एजेंसी

आर्थिक शोध संस्थान एनसीएईआर ने कहा है कि बेहतर ग्लोबल सिनेरियो और सामान्य से अच्छे मानसून की संभावना के चलते चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था सात प्रतिशत से अधिक बढ़ सकती है। 'नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च' (एनसीएईआर) (एनसीएईआर) ने मासिक आर्थिक समीक्षा (एमईआर) के अप्रैल 2024 अंक में कहा कि जीएसटी संग्रह, पीएमआई, बिजली खपत, माल ढुलाई जैसे उच्च आवृत्ति वाले संकेतक घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शा रहे हैं। इसमें विनिर्माण के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) 16 साल के उच्च स्तर पर है और डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई के जरिए लेनदेन भी उच्चतम स्तर पर है। ये दो फैक्टर होंगे अहम एनसीएईआर की महानिदेशक पूनम गुप्ता ने कहा, 'वैश्विक वृद्धि और व्यापार की मात्रा, दोनों में अनुमानित तेजी के साथ ही सामान्य से अच्छे मानसून के पूर्वानुमान से यह संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष के सात प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर हासिल कर सकती है।' एनसीएईआर के अनुसार, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह मार्च में 1.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 2017 में इसके लागू होने के बाद से दूसरा सबसे अच्छा संग्रह है। यूपीआई ने मार्च 2024 में 13.4 अरब लेनदेन (मात्रा में) दर्ज किए, जो इसके लागू होने के बाद से सबसे अधिक है। गुप्ता ने कहा, 'इन हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स के साथ ही आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ के अनुसार बेहतर वैश्विक परिदृश्य के चलते चालू वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत हैं।' इससे पहले अन्य अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत आर्थिक वृद्धि दर सकारात्मक नजरिया रखा है। डेलॉयट इंडिया ने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (उज्ड) की वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है. निर्यात में तेजी और पूंजी प्रवाह इसमें मुख्य कारक रहेंगे।

कुंडली के 12 घर में छिपी है जीवन की झलक, जानें कौन सा भाव क्या बताता है?

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

ज्योतिष शास्त्र में हमारी कुंडली को 12 भावों में बांटा गया है. ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति के जीवन के अलग-अलग पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है. कुंडली से व्यक्ति के भूत, वर्तमान, और भविष्य की स्थिति और घटनाक्रमों के बारे में जानकारी मिलती है. कुंडली में मौजूद बारह भाव जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु से लेकर मोक्ष तक की जानकारी देते हैं. कुंडली का महत्व इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि यह मनुष्य के भविष्य के बारे में बताती है. इससे आप अपने ग्रहों की दशा के बारे में जान सकते हैं. किस ग्रह का असर आपके जीवन पर कब पड़ रहा है इसके बार में भी जान सकते हैं.

कुंडली के 12 भाव

पहला भाव - कुंडली का पहला भाव आपका स्वभाव बताता है.
दूसरा भाव - कुंडली का दूसरा भाव धन और परिवार के बारे में बताता है.
तीसरा भाव - कुंडली का तीसरा भाव भाई-बहन और वीरता के बारे में बताता है.
चौथा भाव - कुंडली का चौथा भाव माता और आनंद भाव के बारे में बताता है.
पंचम भाव - कुंडली का पांचवा भाव संतान और ज्ञान के बारे में बताता है.
छठा भाव -कुंडली का छठा भाव शत्रु और रोग के बारे में बताता है.
सातवां भाव - कुंडली का सातवां भाव विवाह और पार्टनरशिप के बताता है.
आठवां भाव - कुंडली का आठवां भाव आपकी आयु के बारे में बताता है.
नौवां भाव - कुंडली का नवां भाव भाग्य, पिता और धर्म के बारे में बताता है.
दसवां भाव - कुंडली का दसवां भाव करियर और व्यवसाय के बारे में बताता है.
ग्यारहवां भाव -कुंडली का ग्यारहवां भाव आपकी आय और लाभ के बारे में बताता है.
बारहवां भाव - कुंडली का बारहवां भाव आपके व्यय और हानि के बारे में बताता है.

इन राशियों पर चल रही है साढ़ेसाती, शनि गोचर के बाद अब किसकी बारी

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या, वक्री चाल और महादशा आने पर व्यक्ति के जीवन में काफी उथल-पुथल मच जाती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को एक क्रूर ग्रह माना गया है लेकिन किसी जातक की कुंडली में अगर शनि बली होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में हर तरह की खुशी, वैभव और ऐशोआराम की प्राप्ति होती है वहीं अगर जातक की कुंडली में शनि कमजोर होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में परेशानियों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि को आयु, दुख, रोग, सेवक और लोहा का कारक ग्रह माना जाता है। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। शनि तुला राशि में उच्च के और मेष राशि में नीच के होते हैं। सभी ग्रहों में शनि की गति सबसे मंद होती है। शनि की साढ़ेसाती साढ़े साती सात वर्षों तक रहती है। शनि अच्छे कर्म करने वाले जातकों को अच्छा फल जबकि बुरे कर्म करने पर बुरा फल प्रदान करते हैं।

कुंभ राशि में शनि

शनि देव सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह होते हैं। यह एक राशि में करीब ढाई वर्षों तक रहते हैं। शनि अभी कुंभ राशि में विराजमान हैं। आपको बता दें कि 17 जनवरी 2023 को शनि मकर राशि की यात्रा को खत्म करके अपनी दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश किया था तब से अभी इसी राशि में हैं। इसके बाद शनि का राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को होगा जब शनि मीन राशि में गोचर करेंगे और करीब ढाई वर्षों तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे।

शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या

17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में ही मौजूद रहेंगे। शनि के कुंभ राशि में विराजमान होने के कारण मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के ऊपर शनि की साढ़ेसाती है। कुंभ राशि में शनि की साढ़ेसाती होने की वजह से कर्क और वृश्चिक राशि वाले जातकों पर शनि की ढैय्या चल रही है।

मकर राशि पर साढ़ेसाती

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है। मकर राशि पर साढ़ेसाती 26 जनवरी 2017 से शुरू हो गई थी जो अब 29 मार्च 2025 पर खत्म होगी।

कुंभ राशि पर साढ़ेसाती

कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। 23 फरवरी 2028 तक इस राशि के जातकों को साढ़ेसाती से छुटकारा मिल जाएगा।

मीन राशि पर साढ़ेसाती

मीन राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण जारी है। इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती 7 अप्रैल 2030 तक रहेगी।

अगर आप भी कर रहे हैं सूर्यास्त के समय से काम, तो हो जाएं सावधान

श्रीमती नीतू मित्तल
8959760040
ज्योतिषाचार्य, इंदौर (म.प्र.)

हिंदू धर्म में लोग घर में सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए कई तरह के कार्य करते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं, जो हम जाने-अनजाने में कर जाते हैं, लेकिन इन कार्यों को करने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि सूर्यास्त के समय कुछ काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर कोई ऐसा करना है, तो उसकी खुशहाल जिंदगी में कई तरह के संकट आने लगते हैं।

धर्म शास्त्रों में ऐसे काम बताए गए हैं, जिन्हें शाम यानी सूर्यास्त के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय ये काम करने से घर से सुख-समृद्धि चली जाती है। साथ ही व्यक्ति की तरक्की में बाधा आती है और उसे आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है।

धर्म शास्त्रों के अनुसार, सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए। इस समय भोजन करने से व्यक्ति अगले जन्म में पशु के रूप में जन्म लेता है।

किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को सूर्यास्त के समय सोना या लेटना नहीं चाहिए। ऐसे में घर की बरकत चली जाती है। साथ ही धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

सूर्यास्त के समय भगवान की आराधना करने से सकारात्मकता आती है। सूर्यास्त के समय यौन इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस समय पुरुषों और महिलाओं को ऐसी भावनाओं से दूर रहना चाहिए।

शाम के समय जन्म लेने वाले बच्चे को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बताया गया है कि शाम के समय वेदों और शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। इस समय ध्यान और साधना करना ही उत्तम माना जाता है।

सूर्यास्त के समय पैसों का लेन देन करने से बचना चाहिए। ऐसे में घर में पैसों की कमी हो जाती है और खर्चे ज्यादा होने लगते हैं।

सूर्यास्त के समय नाखून नहीं काटने चाहिए और ना ही कभी बाल काटने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में मुश्किलें बढ़ने लगती हैं।

ऐसा जाप जिसमें न कोई नियम न परहेज, लेकिन इसके अनगिनत लाभ आपको चौंका देंगे

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

जाप करने की कई विधियां हैं. शास्त्रों में जाप करने के लिए मुख्य तौर पर तीन प्रकार की विधियों का उल्लेख मिलता है- मानसिक जाप विधि, वाचिक जाप विधि और अपांशु जाप विधि. लेकिन प्रश्न यह है कि किस विधि से किया गया जाप श्रेष्ठ होता है. इस प्रश्न का उत्तर जानने के पहले इन तीनों जाप विधियों के बारे में जान लेते हैं-

मानसिक जापः मानसिक जाप वह होता है जिसमें कोई साधक मंत्रों का उच्चारण बोलकर करने के बजाय मन में करता है. इसे ही मानसिक जाप कहते हैं. इस जाप के दौरान साधक के होंठ तक नहीं हिलते, यहां तक कि पास बैठे लोगों को भी यह मालूम नहीं होता कि, साधक द्वारा मंत्रों का जाप किया जा रहा है.

वाचिक जापः मंत्रों को ऊंचे स्वर में पढ़कर या बोलकर जाप करने की विधि वाचिक जाप कहलाती है. पूजा-पाठ, हवन या कर्म काण्डों के दौरान अधिकतर वाचिक जाप किए जाते हैं.

अपांशु जापः अपांशु जाप वास्तव में मानसिक जाप और वाचिक जाप का मिलाजुला रूप है. इसमें मंत्र को बिना बोले केवल पढ़ा जाता है. इसमें साधक द्वारा बोले गए मंत्र किसी को सुनाई नहीं देते, लेकिन होंठ हिलते हैं, जिससे पता चलता है कि मंत्रों का जाप किया जा रहा है. मानसिक जाप कैसे किया जाता है और इसके क्या आध्यात्मिक या स्वास्थ्य लाभ हैं, जानते हैं-

मानसिक जाप के आध्यात्मिक लाभ

श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, निष्ठा आंतरिक चीजें हैं, जिसे चीख-पुकार कर व्यक्त नहीं किया जा सकता. लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि वाचिक जाप अर्थहीन है. लेकिन आंतरिक भाव का आनंद अमूल्य है.

ईश्वर-प्राणिधान में मानसिक जाप श्रेष्ठ है, क्योंकि जिसका भाव मन लेता है, उस भाव का उच्चारण भी मन कर लेता है. मन ही उस भाव की बात सुनता है.

वेदों में भी प्रार्थना या मंत्रोच्चारण करने की अनेक विधियां बताई गई हैं. ईश्वर हमारे मन के भाव या कुभाव को भली-भांति जानते हैं. इसलिए मात्र शब्दों से न खेंले.

मानसिक जाप के लाभ

इसमें होंठ नहीं हिलती और आंखे बंद होती है. हमारा ध्यान आज्ञा चक्र या ध्यान चक्र में होता है. भगवान का स्वरूप हमारे सामने होता है और हम मन में मंत्र जाप कर रहे होते हैं. ऐसे में मन में भटकाव नहीं होता और धीरे-धीरे मन स्थिर होना शुरू हो जाता है. जैसे ही मन स्थिर होता है हमारी एकाग्रता शुरू हो जाती है और आज्ञा चक्र या हृदय चक्र में स्थित शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त होने लगती है.

जाप में एकाग्रता जरूरी होती है, जोकि मानसिक जाप में होती है. क्योंकि इसमें माला या संख्या में जप नहीं होते. जब हम 108 मंत्रों का जाप या एक माला की जप करते हैं तो माला को मध्यमा ऊंगली पर रखकर ऊंगूठे की मदद से एक-एक मनके को आगे बढ़ाया जाता है. एक मंत्र के पूर्ण होने के बाद दूसरे मनके को आगे बढ़ाना होता है. लेकिन मानसिक जाप में ऐसा नहीं होता है.

मानसिक जाप में आप पूरी एकाग्रता के साथ मन में जाप या ध्यान कर सकते हैं. क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के नियम की बाध्यता नहीं है. यहां तक कि सोते, चलते, यात्रा आदि के दौरान भी जाप का अभ्यास किया जा सकता है. मानसिक जाप सभी दिशाओं और दशाओं में किए जाने का प्रावधान है.

जाप के स्वास्थ्य लाभ

जाप एक प्राचीन प्रथा है, जिसका उपयोग आध्यात्मिक विकास और भावनात्मक विचार को बढ़ावा देने के लिए सदियों से किया जा रहा है. जाप से मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

वर्तमान में विश्व स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं जैसे अवसाद, तनाव, चिंता का स्तर बढ़ रहा है. जाप या मंत्रोच्चारण को स्वास्थ्य लाभ से जोड़ा जाता है. क्योंकि जाप से तनाव को कम करने, एकाग्रता को बढ़ाने और अनिद्रा आदि की समस्या को कम किया जा सकता है.

मनोवैज्ञानिक कल्याण में सुधार के संदर्भ में तनाव कम करने के लिए तकनीक के रूप में मानिसक जाप या ध्यान का उपयोग किया जाता है. हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में भी ऐसी कई परंपराएं हैं, जिससे ध्यान विकसित हुआ है.

मारुति, टाटा, हुंदै या टोयोटो... अप्रैल में किसकी कारें सबसे ज्यादा बिकीं, जानें कौन से मॉडल्स ने मचाई धूम

नई दिल्ली। एजेंसी

ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) की अप्रैल महीने में कुल बिक्री 4.7 प्रतिशत बढ़कर 1,68,089 यूनिट रही। कंपनी ने अप्रैल, 2023 में 1,60,529 वाहन बेचे थे। मारुति सुजुकी इंडिया ने बयान में कहा, 'घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की कुल बिक्री 1,37,952 इकाई रही। जबकि एक साल पहले समान अवधि में यह 1,37,320 इकाई थी। ऑल्टो और एस-प्रेसो सहित छोटी कारों की बिक्री अप्रैल, 2023 के 14,110 इकाई की तुलना में घटकर पिछले महीने 11,519 इकाई रह गई। बलेनो, सेलेरियो, डिजायर, इग्निस, स्विफ्ट, टूर एस और वैगनआर सहित कॉम्पैक्ट कारों की बिक्री भी पिछले महीने घटकर 56,953 इकाई रह गई, जो पिछले साल अप्रैल में 74,935 इकाई थी। ब्रेज़ा, एर्टिगा, एस-क्रॉस और एक्सएल6 जैसे यूटिलिटी वाहनों की बिक्री पिछले महीने 56,553 इकाई रही। जबकि अप्रैल, 2023 में यह 36,754 इकाई थी। अप्रैल में वैन की बिक्री 12,060 इकाई रही, जबकि एक साल पहले यह 10,504 इकाई थी। हल्के वाणिज्यिक वाहन सुपर कैरी की बिक्री अप्रैल, 2023 के 2,199 इकाई से पिछले महीने बढ़कर 2,496 इकाई हो गई। एमएसआई के अनुसार, पिछले महीने उसका निर्यात 22,160 इकाई रहा, जबकि पिछले साल अप्रैल में यह 16,971 इकाई रहा था।

टाटा मोटर्स की बिक्री 11.5% बढ़ी

टाटा मोटर्स की कुल थोक बिक्री सालाना आधार पर 11.5 प्रतिशत बढ़कर 77,521 इकाई हो गई। अप्रैल 2023 में यह 69,599 इकाई थी। मोटर वाहन विनिर्माता ने एक बयान में कहा, कंपनी की कुल घरेलू आपूर्ति पिछले महीने 12 प्रतिशत बढ़कर 76,399 इकाई रही, जो अप्रैल 2023 में 68,514 इकाई थी। कुल यात्री वाहनों की बिक्री पिछले महीने दो प्रतिशत बढ़कर 47,983 इकाई हो गई, जो अप्रैल 2023 में 47,107 इकाई थी। अप्रैल 2024 में कुल वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 29,538 इकाई रही, जो अप्रैल 2023 की 22,492 इकाई की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है।

हुंदै मोटर इंडिया की थोक बिक्री 9.5%बढ़ी

ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनी हुंदै मोटर इंडिया की थोक बिक्री अप्रैल में सालाना आधार पर 9.5 प्रतिशत बढ़कर 63,701 इकाई हो गई। वाहन विनिर्माता ने अप्रैल 2023 में 58,201 इकाइयों की बिक्री की थी। घरेलू थोक बिक्री अप्रैल में एक प्रतिशत बढ़कर 50,201 इकाई हो गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 49,701 इकाई थी। इस साल अप्रैल में निर्यात 59 प्रतिशत बढ़कर 13,500 इकाई हो गया, जबकि अप्रैल 2023 में यह 8,500 इकाई था। हुंदै मोटर इंडिया के मुख्य परिचालन अधिकारी (एमओ) तरुण गर्ग ने कहा कि कंपनी ने इस साल लगातार चौथे महीने 50,000 से अधिक की घरेलू बिक्री दर्ज की। उन्होंने कहा कि क्रेटा, वेन्यू और एक्सटर जैसे मॉडल के दम पर एसयूवी सेगमेंट का घरेलू बिक्री में योगदान 67 प्रतिशत रहा।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की बिक्री 32% बढ़ी

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की अप्रैल महीने में थोक बिक्री सालाना आधार पर 32 प्रतिशत बढ़कर 20,494 इकाई हो गयी। कंपनी ने अप्रैल 2023 में 15,510 इकाई बेची थी। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने एक बयान में कहा कि परिचालन क्षमता, उत्पादकता और सुरक्षा को बनाए रखने के वास्ते मशीनरी तथा उपकरणों के रखरखाव के लिए छह अप्रैल से एक सप्ताह के रखरखाव बंद के बावजूद वृद्धि गति बरकरार रही। कंपनी ने कहा कि पिछले महीने उसकी घरेलू बिक्री 18,700 इकाई रही, जबकि निर्यात कुल 1,794 इकाई रहा। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के अध्यक्ष सबरी मनोहर ने कहा, "हमारी उत्पाद रणनीति विविध सेगमेंट के दम पर बाजार के साथ मजबूत संबंध को दर्शाती है।"

एमजी मोटर की बिक्री 1.45%घटी

एमजी मोटर्स इंडिया की अप्रैल महीने में खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 1.45 प्रतिशत घटकर 4,485 इकाई रह गई। कंपनी ने अप्रैल 2023 में 4,551 इकाइयां बेची थीं। कंपनी ने कहा कि इस अवधि में बेची गई कुल इकाइयों में उसके ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) सेगमेंट का योगदान 34 प्रतिशत रहा।

गुरुग्राम-नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना अब ज्यादा फायदेमंद

इस कारण निवेशकों की हो रही तगड़ी कमाई

एजेंसी

गुरुग्राम-नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना अब पहले से ज्यादा फायदेमंद हो गया है। इसकी वजह यह है कि अब प्रॉपर्टी पर मिलने वाला रेंटल आय में बढ़ोतरी हुई है। संपत्ति सलाहकार एनारॉक की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुग्राम और नोएडा में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर मिलने वाला किराया बढ़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, बीती मार्च तिमाही के दौरान इसमें क्रमशः 4.1 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। किसी संपत्ति में निवेश की गई पूंजी पर निवेशकों को मिलने वाली वार्षिक आय (आरओआई) को किराया आय कहते हैं।

इन शहरों में बढ़ा औसत किराया

एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख शहरों में औसत किराया बढ़ गया है और किराया आय लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों से पता चला कि जनवरी-मार्च 2024 के दौरान 4.45 प्रतिशत की किराया आय के साथ बेंगलुरु सूची में सबसे ऊपर है। कोविड महामारी से पहले 2019 में बेंगलुरु में किराया आय 3.6 प्रतिशत थी। शीर्ष शहरों में इसके बाद 4.15 प्रतिशत के साथ मुंबई दूसरे स्थान पर है। इसके बाद गुरुग्राम का स्थान है। आंकड़ों के अनुसार, मार्च तिमाही में किराया आय नोएडा में 3.7 प्रतिशत, दिल्ली में 2.9 प्रतिशत, पुणे में 3.85 प्रतिशत और नवी मुंबई में 3.4 प्रतिशत थी।

आने वाले समय में और बढ़ेगा रिटर्न

दिग्गज रियल्टी एक्सपर्ट और अंतरिक्ष इंडिया के सीएमडी राकेश यादव ने कहा कि प्रॉपर्टी पर मिलने वाला निवेश आने वाले समय में और बढ़ना तय है। उन्होंने कहा कि अब रियल एस्टेट एक इंडस्ट्री की तौर पर काम कर रही है। लोगों का भरोसा इस सेक्टर पर बढ़ा है। वहीं, बेहतर लाइफस्टाइल की चाह ने सोसाइटी कल्चर को बढ़ाया है। इसके चलते लोग अधिक कीमत देकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या ज्यादा रेंटल चुकाकर अच्छे लोकेशन पर बड़े साइट के फ्लैट किराया पर ले रहे हैं। यह ट्रेंड आने वाला समय में और बढ़ना तय है। वहीं, सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए जा रहे निवेश का फायदा रियल्टी सेक्टर को लगातार मिल रहा है। इन सब कारणों से प्रॉपर्टी में किया निवेशक आकर्षक रिटर्न दिलाने का काम करेगा।

टाटा मोटर्स ने नवाचार की रफ्तार तेज़ की

वित्त वर्ष 2024 में रिकॉर्ड 222 पेटेंट्स दर्ज कराये और 333 अनुदान प्राप्त किये ऑटोमोटिव उत्कृष्टता के लिये इंडस्ट्री में एक नई मिसाल कायम की

आईपीटी नेटवर्क

भारत की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के निर्माण की दिशा में एक बार फिर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वित्त वर्ष 24 के दौरान कंपनी ने रिकॉर्ड-ब्रेकिंग 222 पेटेंट और 117 डिजाइन आवेदन दायर किए गए, जो इसके इतिहास में सर्वोच्च है। ये फाइलिंग उत्पाद और प्रक्रिया नवाचारों के एक व्यापक क्षेत्र में फैली हुई हैं, जो कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन, स्थिरता और सुरक्षा (सीईएसएस) जैसे प्रमुख ऑटोमोटिव मेगाट्रेंड को संबोधित करती हैं। ये विभिन्न वाहन प्रणालियों को भी कवर करती हैं जैसे कि पावरट्रेन, बॉडी और ट्रिम, सस्पेंशन, ब्रेक, एचवीएसी और उत्सर्जन नियंत्रण। टाटा मोटर्स को उसी अवधि के दौरान अब तक का सबसे अधिक 333 पेटेंट का अनुदान भी प्राप्त हुआ, जिससे उसके स्वीकृत पेटेंट की कुल संख्या 850 से अधिक हो गई।

इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, स्वच्छ पावरट्रेन, डिजाइन कनेक्टिविटी और बुद्धिमान सुरक्षा सुविधाओं के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता के साथ, टाटा मोटर्स यह सुनिश्चित करता है कि उसके नवाचार वास्तविक दुनिया की जरूरतों के साथ सहजता से

जुड़ें। उपभोक्ता कल्याण और पर्यावरण संरक्षण दोनों को प्राथमिकता देकर, कंपनी के उद्देश्यपूर्ण अनुसंधान और नवाचार प्रयासों ने अधिक कुशल, हरित और सुरक्षित वाहनों का उत्पादन किया है। इससे अंतिम उपयोगकर्ताओं को लाभ हुआ है और उद्योग में बदलाव आया है। वित्त वर्ष 2024 में, टाटा मोटर्स को बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) में अपनी उत्कृष्टता के लिए वैश्विक ख्याति के पांच प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार मिले। इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये, टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट एवं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर राजेन्द्र पेटकर ने कहा, "अनुसंधान एवं नवाचार के प्रति टाटा मोटर्स की अटूट प्रतिबद्धता ने हमें बौद्धिक संपत्ति के माध्यम से नवाचार एवं मूल्य निर्माण में नये मुकाम हासिल करने के लिये प्रेरित किया है। रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट दायर करने और अनुदान प्राप्त करने के साथ, हम लगातार ऑटोमोटिव उत्कृष्टता को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। हमारी अत्याधुनिक तकनीकें, पर्यावरण हितैषी वाहन और ग्राहक केन्द्रित प्रयासों की बदौलत हमने इंडस्ट्री में एक खास मुकाम हासिल किया है। जैसे-जैसे गतिशीलता विकसित हो रही है, टाटा मोटर्स सबसे आगे है, सभी के लिए एक स्मार्ट, अधिक जुड़े भविष्य को आकार दे रही है।'

शक्ति पंप्स ने हासिल किया अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट

वित्तीय वर्ष 24 में 142 करोड़ रहा शुद्ध लाभ

पीथमपुर। आईपीटी नेटवर्क

सोलर स्टेनलेस-स्टील सबमर्सिबल पंप, प्रेशर बूस्टर पंप, पंप-मोटर्स, कंट्रोलर और इनवर्टर सहित अन्य उत्पादों के अग्रणी निर्माता शक्ति पंप्स (इंडिया) लिमिटेड ने 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की। शक्ति पंप्स (इंडिया) लिमिटेड के चेयरमैन दिनेश पाटीदार ने कंपनी के प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि, 'FY24 शक्ति पंप्स (इंडिया) लिमिटेड के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष रहा है, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में अब तक का मजबूत प्रदर्शन किया है। यह हमारी गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट बिजनेस दोनों में हमारे उत्कृष्ट प्रदर्शन को बताता है, जिसने FY24 में क्रमशः 52% और 23% की रेवेन्यु में ग्रोथ दर्ज की है। हमारी प्रभावशाली ऑर्डर बुक, राशि 2,400 करोड़ रुपये, 31 मार्च 2024 तक हाल ही में 250.62 करोड़ रुपये के तीन नए ऑर्डर के साथ जनवरी 2024 की शुरुआत से हरियाणा और महाराष्ट्र में विस्तारित हुआ है। शक्ति पंप्स (इंडिया) लिमिटेड अपने ऑर्डर बुक के निरंतर विस्तार के बारे में आशावादी है, जो कृषक समुदाय के बीच सोलर पंपों को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। तिमाही के दौरान कंपनी ने सफलतापूर्वक 200 करोड़ रुपये क्यूआईपी के माध्यम दो प्रमुख म्यूचुअल फंडों से प्राप्त किये है। इन राशियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पंप/मोटर्स, इनवर्टर/वीएफडी और सहायक स्ट्रक्चर की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाएगा। रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रति हमारा अटूट समर्पण है, क्योंकि हम खुद को एक इनोवेशन केंद्रित इंटरप्राइजेज के रूप में परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। यह प्रतिबद्धता हमारे द्वारा हाल ही में हासिल किए गए दो अतिरिक्त पेटेंटों से प्रमाणित होती है, जिसमें फाइल किए गए 29 में से हमें कुल 13 पेटेंट प्राप्त हो गए हैं। सोलर पीएम कुसुम योजना के नेतृत्व में पंप उद्योग, 14 लाख से अधिक ऑफ-ग्रिड और 35 लाख से अधिक ऑन-ग्रिड सोलर पंपों की अनुमानित स्थापना डिमांड के साथ डेवलपमेंट के लिए तैयार है। विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने खेतों की सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। जिसमे डिस्कॉम को बेसिक स्ट्रक्चर उपलब्ध कराने में कॉस्ट शामिल होती है, साथ ही बिजली कम रियायती दरों पर उपलब्ध करानी होती है, जो डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति पर और अधिक बोझ डालती है।

इसके बावजूद, कई किसान बिजली कनेक्शन से वंचित रह जाते हैं और उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। राज्य और केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से 60-70% कॉस्ट को कम करने के साथ, सब्सिडी वाले सोलर पंपों के बदलाव से, सरकार को एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। यह पहल केवल 2-3 वर्षों में किसानों को विश्वसनीय बिजली प्रदान करते हुए, स्थिरता की ओर ले जाते हुए, बचत के साथ सब्सिडी को संतुलित करती है। रणनीतिक रूप से मजबूत, शक्ति पंप्स (इंडिया) लिमिटेड निरंतर विकास के लिए तैयार है, ऑर्डर में अनुमानित वृद्धि का लाभ उठाने और संभावित अवसरों के लिए खुद को उपयुक्त स्थिति में लाने के लिए तैयार है। इन उत्साहवर्धक विकासों के साथ, हम भविष्य में अपने सभी शेयर होल्डरों के लिए लगातार मजबूत परिणाम देने की अपनी क्षमता में विश्वास रखते हैं।

सैमसंग इंडिया ने 'सैमसंग इनोवेशन कैंपस' का दूसरा सीजन लॉन्च किया

नेशनल स्किलिंग प्रोग्राम है, जिसका मकसद युवाओं को फ्यूचर-टेक डोमेन में सशक्त बनाना

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग ने अपने राष्ट्रीय कौशल प्रोग्राम - सैमसंग इनोवेशन कैंपस - के दूसरे सीजन को लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य एआई, आईओटी, बिग डेटा और कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग जैसे भविष्य के तकनीकी डोमेन में युवाओं को कुशल बनाने के लिए तैयार किया गया है। सैमसंग इनोवेशन कैंपस का लक्ष्य 18-25 वर्ष की आयु के युवाओं को भविष्य की तकनीकों में कुशल बनाना और उनकी रोजगार क्षमता को बेहतर करना है। यह प्रोग्राम भारत की विकास गाथा में एक मजबूत भागीदार और योगदान की दिशा में सैमसंग की प्रतिबद्धता को सामने लाता है है। इसे युवाओं के लिए सही अवसर पैदा करने के लिए स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी भारत सरकार की पहल का समर्थन करने के लिए तैयार किया गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में सैमसंग और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया (ईएसएससीआई) के बीच भारत भर में 3,500 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस वर्ष यह प्रोग्राम केवल कौशल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं होगा, बल्कि उससे आगे बढ़कर छात्रों के लिए और अधिक रोमांचक अवसरों को सामने लेकर आएगा। प्रत्येक डोमेन के राष्ट्रीय टॉपर्स को 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा और साथ ही दिल्ली/एनसीआर में सैमसंग केंद्रों का दौरा करने का अवसर भी मिलेगा। इन केंद्रों का दौरा करने से छात्रों को सैमसंग की नेतृत्व टीम के साथ बातचीत करने और उनसे सीखने व समझने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के टॉपर्स को सैमसंग गैलेक्सी बड्स और सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टवॉच जैसे रोमांचक सैमसंग उत्पाद भी मिलेंगे।

रियलमी ने नार्ज़ो श्रृंखला का विस्तार करते हुए रियलमी नार्ज़ो 70 सीरीज़ 5जी पेश किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

सबसे विश्वसनीय स्मार्टफोन सेवा प्रदाता, रियलमी ने आज रियलमी नार्ज़ो श्रृंखला में रियलमी नार्ज़ो 70 सीरीज़ 5जी का लॉन्च किया। इस सीरीज़ में दो अत्याधुनिक स्मार्टफोनः रियलमी नार्ज़ो 70एक्स 5जी और रियलमी नार्ज़ो 70 5जी पेश किए गए हैं। रियलमी नार्ज़ो स्टाईलिश स्मार्टफोंस की सीरीज़ है, जो यूज़र्स को विस्तृत अनुभव प्रदान करती हैं। भारत में स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के भविष्य का प्रतिनिधित्व करने वाली रियलमी नार्ज़ो सीरीज़ का उपयोग करने वाले यूज़र्स की संख्या 16 मिलियन से ज्यादा है। इस लॉन्च के बारे में रियलमी के प्रवक्ता ने कहा हमें रियलमी नार्ज़ो 70 सीरीज़ 5जी के लॉन्च की घोषणा करने की खुशी है यह यूज़र्स को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी एवं प्रीमियम फीचर्स प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है यह सीरीज़ स्मार्टफोन के भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है जो यूज़र्स को लगातार विकसित होते हुए डिजिटल परिदृश्य में संपूर्ण अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाईन की गई है। अपनी आधुनिक और शक्तिशाली विशेषताओं के साथ रियलमी नार्ज़ो 70 सीरीज़ 5जी स्मार्टफोन के अनुभव को बदल देगी। भारत में 16 मिलियन से ज्यादा यूज़र्स तक पहुँचकर अपने कदमों का विस्तार करते हुए हमें विश्वास है कि रियलमी नार्ज़ो 70 सीरीज़ 5जी स्मार्टफोन उद्योग में नए मानक स्थापित कर देगी। रियलमी नार्ज़ो 70 सीरीज़ 5जी के साथ कनेक्टिविटी और परफॉर्मेंस का नया युग शुरू करने की तैयारी कर लीजिए।''

भारतीयों के लिए जर्मनी बना पसंदीदा डेस्टिनेशन, 2023 में टूरिस्ट की संख्या 32.6 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली। एजेंसी

जर्मनी के टूरिज्म इंडस्ट्री में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। इस ग्रोथ को आगे बढ़ाने में भारतीय टूरिस्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साल 2023 में जर्मनी ने भारत से आए 8 लाख से अधिक टूरिस्ट का स्वागत किया गया, जो पिछले वर्षों की तुलना में जर्मन टूरिज्म में एक बड़ी वृद्धि को दर्शाता है।यह जर्मनी के टूरिज्म इंडस्ट्री द्वारा सस्टेनेबल और ट्रैवल फ्रेंडली डेस्टिनेशन के साथ कल्चरल एक्सपीरिएंस की पेशकश को भी दर्शाता है. यही वजह है कि चाहे वे भारत के हों या विश्व के किसी भी कोने से, जर्मन टूरिज्म सभी यात्रियों का मन मोह लेती है। जर्मन नेशनल टूरिस्ट ऑफिस (GNTO) और जर्मन एम्बेसी (German Embassy in India) ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें जर्मनी को भारतीय यात्रियों के लिए पसंदीदी डेस्टिनेशन के रूप में बताया है. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली स्थित जर्मन दूतावास (German Embassy) में आयोजित की गई थी। हाल के वर्षों में, जर्मनी में भारतीय पर्यटकों (Indian Tourists) की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है.इसके साथ ही देश उनका सबसे पसंदीदा ट्रैवल डेस्टिनेशन बन गया है। बता दें कि 2022 की तुलना में जर्मनी की यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या में 32.6% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह भारतीय यात्रियों के बीच जर्मनी की समृद्ध संस्कृति, सुंदर नजारे, ऐतिहासिक स्थल आदि में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। इसको लेकर जर्मन नेशनल टूरिस्ट ऑफिस (GNTO) के निदेशक रोमित थियोफिलस ने कहा 'हमें यह देखकर खुशी हो रही है कि जर्मनी को अपने पसंदीदी डेस्टिनेशन के रूप में चुनने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है।'

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।